

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

डॉ० मधु खरे

सदस्य

विविध प्रकरण क्रमांक 844-दो/2011

महिला हरदीप कौर पत्नि सुखवीर सिंह
ग्राम खरवाया (चकगढ़ला) तहसील
पोहरी जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश

---आवेदक

विरुद्ध

- 1- अरुण सिंह पुत्र बलवीर सिंह
- 2- कमलजीत सिंह पुत्र बसबिंदर सिंह
- 3- गुरुजीत सिंह पुत्र अमरीक सिंह
मुख्त्यारआम अमरीकसिंह पुत्र
श्रीपाल सिंह सरदार
- 4- राज सुरेन्द्र कौर पुत्री जसबंतसिंह
सभी निवासी ग्राम खरवाया(चकगढ़ला)
तहसील पोहरी जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश

---अनावेदकगण

(श्री कुँवर सिंह कुशवाह अभिभाषक - आवेदक)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

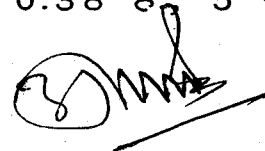
अ त द श

(आज दिनांक 5 नवम्बर 2015 को पारित)

न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 1014/III/2008 में पारित
अंतरिम आदेश दिनांक 02.09.2008 का अनावेदकगण द्वारा
पालन नहीं करना बताते हुये न्यायालय अवमान अधिनियम, 1977
की धारा 10 सहपठित 12 के अंतर्गत यह आवेदन विविध आवेदन
प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार पोहरी
के समक्ष म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 190/110 के
अंतर्गत आवेदन देकर मांग की कि ग्राम खरवाया स्थित भूमि सर्वे
क्रमांक 3 रकबा 0.95 है., 4 रकबा 0.38 है, 5 रकबा 0.43 है.

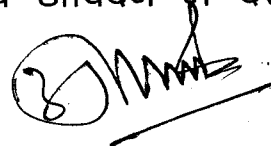
01



7 रकबा 15 है., 8 रकबा 0.15 है. कुल किता 5 कुल रकबा 2.06 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर उसका 20 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है इसलिये संहिता की धारा 190/110 के अंतर्गत उसे भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो चुके हैं , भूमिस्वामी घोषित कर नामान्तरण किया जावे। तहसीलदार पोहरी ने प्रकरण क्रमांक 1/99-2000/31-46 में पारित आदेश दिनांक 29.6.2000 से वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का नामान्तरण किया। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक क-1 से 3 ने अनुविभागीय अधिकारी, पोहरी के समक्ष अपील क्रमांक 4/04-05 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 12-3-2007 से अपील अस्वीकार हुई। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील क्रमांक 199/2006-07 प्रस्तुत होने पर आदेश दि. 30.7.08 से अपील स्वीकार की गई एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये अनावेदक क. 1 से 3 के हक में वादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण करने के निर्देश दिये गये। इस आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 1014/III/2008 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 02.09.2008 से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर स्थगन दिया गया। आवेदक के विविध आवेदन के तथ्यों अनुसार अनावेदकगणों को स्थगन की जानकारी होने के बाद भी दिनांक 6-10-2010 को वादग्रस्त आराजी महिला प्रीतकमल पुत्री कमलजीत सिंह सिक्ख को विक्रय कर दी गई एवं ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण भी कर दिया गया। आवेदक द्वारा विविध आवेदन प्रस्तुत कर अनावेदक क्रमांक 1,2,3 द्वारा अंतरिम आदेश दि. 02.09.08 की अवज्ञा करना बताते हुये यह विविध आवेदन दिया गया है।

4/ अवमानना वावत् प्रस्तुत विविध आवेदन में दर्शाए गए

01



तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने एवं प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण क्रमांक 1014-तीन/2008 निगरानी में दिनांक 2-9-08 को अंतरिम आदेश इस प्रकार दिया गया है :-

- आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह को ग्राह्यता एवं स्थगन के बिंदु पर सुना गया।
- २- निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाती है अभिलेख तलब हों। अनावेदक आहुत हो। अन्य आदेश तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है।
- 3- प्रकरण दिनांक 23-10-08 को पेश हो। *

दिनांक 02-09-2008 को अनावेदक उपस्थित नहीं है अर्थात् एकपक्षीय रूप से स्थगन दिया गया था। आवेदक के अभिभाषक ने विविध आवेदन में दिये गये विवरण वावत् मौखिक तर्कों में बताया कि उन्होंने अंतरिम आदेश दिनांक 2-9-08 की सूचना तहसील में एवं ग्राम पंचायत में दी है फिर भी ग्राम पंचायत ने नामान्तरण करने में भूल की है इसी प्रकार अपर आयुक्त के आदेश का अमल शासकीय अभिलेख में करने में भी भूल की गई है, परन्तु आवेदक के अभिभाषक अंतरिम आदेश दिनांक 2-9-08 के तहसील में अथवा ग्राम पंचायत में दिये जाने वावत् कोई दस्तावेज पुष्टिकरण में प्रस्तुत नहीं कर सके हैं जिससे यह परिलक्षित होता हो कि आवेदक ने अंतरिम आदेश दिनांक 2-9-08 की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ तहसील में एवं ग्राम पंचायत में यथा-समय दे दी हैं , जिसके कारण आवेदक अभिभाषक द्वारा अवमानना वावत् दिये गये विविध आवेदन के तथ्य संदेह की परिधि में हैं। इसके अतिरिक्त अवमानना आवेदन में स्थगन आदेश होते हुये भी नामान्तरण/ विक्रय पत्र सम्पादित करने के लिये तहसील, ग्राम पंचायत तथा


9



उप पंजीयक को जिम्मेदार बताया है परन्तु यह अवमानना याचिका अनावेदकगणों के विरुद्ध लाई गई है। तहसील, ग्राम पंचायत, उप पंजीयक के विरुद्ध अवमानना याचिका नहीं लगाई है और न ही उन्हें पक्षकार बनाया है। स्थगन एकपक्षीय दिया गया था, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अनावेदकगणों को स्थगन आदेश की जानकारी कब हुई थी। जिन अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना सम्बन्धी कार्यवाही चाही है, उन्हें पक्षकार भी नहीं बनाया गया है, जिसके कारण आवेदक की ओर से प्रस्तुत विविध आवेदन विचार योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 10 सहपठित 12 के अंतर्गत प्रस्तुत यह विविध आवेदन इसी-स्तर पर अमान्य किया जाता है।




(डॉ० मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म०प्र०ग्वालियर